

प्रदेश में हलाल लखि उत्पादों की बकिरी पर प्रतबिंध

चर्चा में क्यों?

18 नवंबर, 2023 को उत्तर प्रदेश में किसी भी उत्पाद पर हलाल प्रमाणन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। यह पाबंदी खाद्य उत्पाद के साथ ही दवाओं पर भी लागू होगी।

प्रमुख बदि

- उत्तर प्रदेश की खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन वभाग की अपर मुख्य सचवि अनीता सहि ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सभी खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों को नरितर नगिरानी के नरिदेश दयि गए हैं।
- खाद्य उत्पाद के साथ ही दवाओं के उत्पाद के नरिमाण, भंडारण, वतिरण एवं वकिरय पर पूरी तरह से प्रतबिंध रहेगा। हालाँकि विदेशि भेजे जाने वाले उत्पाद के लयि छूट रहेगी।
- वदिति हो क विदेशि में नरियात होने वाले मांस और उससे नरिमति उत्पादों पर हलाल प्रमाण पत्र जारी होता रहा है। धीरे-धीरे तेल, साबुन, घी सहति सभी उत्पादों पर हलाल प्रमाणन की मुहर लगने लगी। मुख्यमंतरी योगी आदतियनाथ के नरिदेश के बाद इसे रोकने की रणनीति बिनाई गई और 18 नवंबर को इस पर प्रदेश में पाबंदी लगा दी गई है।
- प्रदेश में हलाल प्रमाणन वाले किसी भी खाद्य उत्पादों एवं दवाओं को स्वीकार नहीं कयि जाएगा। यद कि कोई उत्पादन हलाल प्रमाणन वाला पाया गया तो संबंधति नरिमाता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नरिमाण के साथ ही भंडारण, वतिरण, वकिरय पर पूरी तरह से प्रतबिंध लगा दिया गया है।
- यद राज्ज में कार्यरत कोई नरियातक अपने खाद्य उत्पाद अथवा दवा को उन देशों के लयि तैयार करता है, जहाँ हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पाद ही स्वीकार कयि जाते हैं तो उसे छूट दी जाएगी। वह दूसरे देश के लयि तैयार होने वाले उत्पाद का नरिमाण, भंडारण एवं वतिरण कर सकेगा।
- प्रदेश की नयिमावली में हलाल प्रमाणीकरण का कोई नयिम नहीं है। सरिफ गुणवत्ता, पैकगि, लेबलगि सही होनी चाहयि। नए आदेश के बाद यद कि कोई हलाल प्रमाणीकरण युक्त दवाओं, प्रसाधन सामग्री व खाद्य सामग्री तैयार करता है अथवा भंडारण व वतिरण करता है तो उसके खिलाफ अधनियिम 1940 व तत्संबंधी नयिमावली के अधीन कार्रवाई की जाएगी।
- इसके तहत तीन साल का कारावास, एक लाख रुपए जुर्माना, और नयिम 18 ए के तहत छह साल का कारावास अथवा 25 हज़ार का जुर्माना हो सकता है।